

राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप-4) विभाग

एफ. 5(11)आयो./ग्रुप-4/2019

जयपुर, दिनांक 10.12.2019

योजनाओं को सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) एवं संबंधित Targets के साथ Map किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश

विषय:- राज्य में संचालित समस्त केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं में प्रस्तावित प्रावधानों (आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-2021 एवं संशोधित अनुमान वर्ष 2019-2020) को 17 सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) एवं संबंधित 169 Targets के साथ Map किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ:- वित्त विभाग द्वारा जारी बजट परिपत्र क्रमांक प.4(36)वित्त-1(1)आ.व्य./2019 दिनांक 05.09.2019 (पैरा-3)।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा माह सितम्बर, 2015 में वैश्विक स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) को भारत सहित सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाये जाने का निर्णय किया गया। ये लक्ष्य जनवरी, 2016 से लागू किये गये हैं। इनका उद्देश्य वर्ष 2030 तक दुनिया भर में गरीबी को सभी आयामों में समाप्त करना और सबके लिये एक समान, न्यायपूर्ण एवं सुरक्षित विश्व का निर्माण करना है।

राष्ट्रीय स्तर पर देश में सतत् विकास लक्ष्यों की क्रियान्विति का उत्तरदायित्व नीति आयोग को प्रदान किया गया है। आयोग द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की Mapping सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) एवं इनसे संबंधित Targets के साथ कर राज्यों से ये अपेक्षा की है कि राज्य भी राज्य स्तर पर समस्त संचालित योजनाओं की Mapping इन लक्ष्यों एवं संबंधित Targets के साथ करावे। साथ ही राज्यों से यह भी अपेक्षा की गई है कि राज्य अपनी योजनाओं के बजट प्रावधानों को सतत् विकास के लक्ष्यों से Map करावे।

वैश्विक विकास की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूत्रित (Formulated) सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) एवं इनसे संबंधित Targets को अर्जित किये जाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य में संचालित समस्त केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं एवं राज्य योजनाओं में प्रस्तावित प्रावधानों को 17 सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) एवं संबंधित 169 Targets के साथ सम्बद्ध (Align) किया जाना है। चूंकि 17 सतत् विकास लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं तथा एक लक्ष्य को अर्जित किये जाने हेतु किये गये प्रयास अन्य एक या एक से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने में सहयोगी है या प्रभावित करते हैं। अतः विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके विभाग द्वारा संचालित समस्त केन्द्रीय एवं

राज्य योजनाओं में प्रस्तावित प्रावधानों को 17 Key SDGs, अन्य सहयोगी लक्ष्यों (Associated SDGs) एवं संबंधित Targets के साथ Map किया जावे।

अतः समस्त विभागों/संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि वह विभाग/संस्था द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों को सतत् विकास लक्ष्यों को अर्जित किये जाने की दृष्टि से Align करावे। विभाग इन योजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों हेतु संशोधित अनुमानों वर्ष 2019-20 व बजट अनुमान वर्ष 2020-21 में रखे जाने वाले प्रावधानों को 17 सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) एवं संबंधित 169 Targets के विरुद्ध दर्शाया जाना सुनिश्चित करे।


उक्तानुसार बजट प्रावधानों की सूचना IFMS पर भी उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है। इस हेतु IFMS पर एक Module/Interface तैयार किया जा रहा है। IFMS पर वर्तमान में संचालित समस्त योजनाओं को Map किये जाने का कार्य आयोजना विभाग स्तर पर सम्पादित किया जाना है। समस्त विभागों से यह अपेक्षित है कि वह वर्तमान में संचालित योजनाओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में तैयार करावे।

नई योजनाओं/बजट शीर्षों को सतत् विकास लक्ष्यों एवं संबंधित Targets के साथ Map किये जाने हेतु नवीन बजट मद खोले जाने के लिये निर्धारित प्रपत्र-7 को वित्त विभाग के अनुमोदन से संशोधित किया गया है।

17 सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) एवं संबंधित 169 Targets का विवरण (परिशिष्ट-2 व 3) तथा आयोजना विभाग स्तर पर वर्तमान योजनाओं की सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ की गई Draft mapping सन्दर्भ हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की Website (<http://plan.rajasthan.gov.in/statistics>) पर दिये गये 'SDG 2030' link पर उपलब्ध कराई गई है।

अतः समस्त बजट आकलन अधिकारियों तथा नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभाग द्वारा संचालित समस्त केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं राज्य योजनाओं में प्रस्तावित प्रावधानों को 17 सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) एवं संबंधित 169 Targets के साथ सम्बद्ध (Align) किया जाना सुनिश्चित करावे। इस हेतु विभाग वर्तमान संचालित समस्त योजनाओं की सूचना परिशिष्ट-1 में दिनांक 31.12.2019 तक आयोजना विभाग को उपलब्ध करावे तथा योजनागत प्रावधानों अन्तर्गत नवीन योजनाओं हेतु बजट शीर्ष खोले जाने एवं वर्तमान संचालित योजनाओं में नवीन बजट शीर्ष खोले जाने के प्रस्ताव संशोधित प्रारूप (प्रपत्र-7) में यथासमय आयोजना/वित्त विभाग को प्रस्तुत करावे।

संलग्न: परिशिष्ट-1 व संशोधित प्रपत्र-7


(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, आयोजना

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय
2. योजनागत प्रावधानों से संबंधित समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
3. शासन सचिव, वित्त (बजट)/विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय), वित्त विभाग
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव
5. प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार
7. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
3. निदेशक, बजट, वित्त विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि वित्त विभाग द्वारा जारी बजट परिपत्र दिनांक 05.09.2019 के क्रम में उक्त दिशा-निर्देशों को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
4. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को प्रेषित कर लेख है कि दिशा-निर्देश को आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की वेबसाईट पर दिये गये 'SDG 2030' link पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
5. उप निदेशक, आयोजना (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि दिशा-निर्देश को आयोजना विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

विशेषाधिकारी, आयोजना

परिशिष्ट-1

योजनाओं को सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) एवं Targets से Map किये जाने हेतु प्रपत्र

विभाग का नाम :

क्र. सं.	योजना का नाम एवं योजना कोड (Name of the Scheme and Scheme Code)	के. प्र. योजना/ राज्य योजना (CSS/State Scheme)	योजना के मुख्य उद्देश्य (Key objective of the Scheme)	लक्षित लाभार्थी समूह (Target Beneficiary Group)	मुख्य संबंधित सतत् विकास लक्ष्य (Key SDGs)*	अन्य संबंधित सतत् विकास लक्ष्य (Other associated SDGs)**	मुख्य संबंधित सतत् विकास टारगेट (Key SDG Targets)@	अन्य संबंधित सतत् विकास टारगेट (Other associated SDG Targets)@@
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* कॉलम नम्बर 6 में योजना से संबंधित मुख्य सतत् विकास लक्ष्य का कोड नम्बर (1 से 17 में से कोई एक) अंकित किया जाना है। यदि योजना इन 17 लक्ष्यों से कोई लक्ष्य संबंधित नहीं है तो कोड नम्बर 18 अंकित किया जाना है। सतत् विकास लक्ष्यों की सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

** कॉलम नम्बर 7 में योजना से संबंधित अन्य सतत् विकास लक्ष्यों का/के कोड नम्बर (1 से 17) अंकित किये जावें। एक योजना में अन्य संबंधित सतत् विकास लक्ष्य एक से अधिक हो सकते हैं अतः संबंधित सभी लक्ष्यों के कोड अंकित किये जावें।

@ कॉलम नम्बर 8 में योजना जिस मुख्य सतत् विकास लक्ष्य से संबंधित है (कॉलम 6 अनुसार) तो उस लक्ष्य से संबंधित Targets के कोड नम्बर जो 1 से अधिक हो सकते हैं उनको अंकित किया जावे। सतत् विकास लक्ष्यों के टारगेट की सूची परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

@@ कॉलम नम्बर 9 में योजना यदि मुख्य सतत् विकास लक्ष्य के साथ अन्य सतत् विकास लक्ष्यों (कॉलम 7 अनुसार) से संबंधित है तो उस संबंधित लक्ष्यों से संबंधित Targets के कोड नम्बर से योजना को अंकित किया जावे।

Revised Budget Head Creation Form (F-7)

BFC Unit Code:

BFC Unit Name:

Expenditure Division:

S. No	Major Head	Sub Major Head	Minor Head	Sub Minor Head With Description	Group Head with Description	Demand No	Controlling Officer Code	Controlling Officer Name	Plan Scheme Code if Exist	Plan Scheme Name	Sector Name / No.	Major Scheme if Exist	Corresponding Receipt Head (13 Digits)	Related SDG No. (1 to 17)	Other Associate SDGs (May be more than 16)	Related SDG Target	Other Associate SDG Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	

Share Scheme Yes/No

If Yes then

Central share (%)	State Share (%)

Order No.:

Order Date :

(Budget Controlling Officer)

(Planning Department)

(JS Expenditure)

(JS Budget)

S.No.	Sustainable Development Goals
1	No Poverty (End poverty in all its forms everywhere)
2	Zero Hunger (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture)
3	Good Health and Well Being (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages)
4	Quality Education (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all)
5	Gender Equality (Achieve gender equality and empower all women and girls)
6	Clean Water and Sanitation (Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all)
7	Affordable and clean Energy (Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all)
8	Decent Work and Economic Growth (Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all)
9	Industry, Innovation and Infrastructure (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation)
10	Reduced Inequalities (Reduce inequality within and among countries)
11	Sustainable Cities and Communities (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable)
12	Sustainable Consumption and Production (Ensure sustainable consumption and production patterns)
13	Climate Action (Take urgent action to combat climate change and its impact)
14	Life Below Water (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development)
15	Life on Land (Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss)
16	Peace, Justice and Strong Institutions (Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels)
17	Partnerships For The Goals (Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development)
18	Others-not related with any SDGs

Sustainable Development Goals : 169 Targets

Target Code	Target Description
1.1	By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than \$1.25 a day
1.2	By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions
1.3	Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable
1.4	By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance
1.5	By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters
1.a	Ensure significant mobilization of resources from a variety of sources, including through enhanced development cooperation, in order to provide adequate and predictable means for developing countries, in particular least developed countries, to implement programmes and policies to end poverty in all its dimensions
1.b	Create sound policy frameworks at the national, regional and international levels, based on pro-poor and gender-sensitive development strategies, to support accelerated investment in poverty eradication actions
2.1	By 2030, end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in vulnerable situations, including infants, to safe, nutritious and sufficient food all year round
2.2	By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the internationally agreed targets on stunting and wasting in children under 5 years of age, and address the nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating women and older persons
2.3	By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers, including through secure and equal access to land, other productive resources and inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for value addition and non-farm employment
2.4	By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve land and soil quality
2.5	By 2020, maintain the genetic diversity of seeds, cultivated plants and farmed and domesticated animals and their related wild species, including through soundly managed and diversified seed and plant banks at the national, regional and international levels, and promote access to and fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources and associated traditional knowledge, as internationally agreed

Target Code	Target Description
2.a	Increase investment, including through enhanced international cooperation, in rural infrastructure, agricultural research and extension services, technology development and plant and livestock gene banks in order to enhance agricultural productive capacity in developing countries, in particular least developed countries
2.b	Correct and prevent trade restrictions and distortions in world agricultural markets, including through the parallel elimination of all forms of agricultural export subsidies and all export measures with equivalent effect, in accordance with the mandate of the Doha Development Round
2.c	Adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity markets and their derivatives and facilitate timely access to market information, including on food reserves, in order to help limit extreme food price volatility
3.1	By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births
3.2	By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live births
3.3	By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases
3.4	By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being
3.5	Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol
3.6	By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents
3.7	By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes
3.8	Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all
3.9	By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination
3.a	Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control in all countries, as appropriate
3.b	Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and non-communicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public health, and, in particular, provide access to medicines for all

Target Code	Target Description
3.c	Substantially increase health financing and the recruitment, development, training and retention of the health workforce in developing countries, especially in least developed countries and small island developing States
3.d	Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk reduction and management of national and global health risks
4.1	By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and Goal-4 effective learning outcomes
4.2	By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care and preprimary education so that they are ready for primary education (2030)
4.3	By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education, including university (2030)
4.4	By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship
4.5	By 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all levels of education and vocational training for the vulnerable, including persons with disabilities, indigenous peoples and children in vulnerable situations
4.6	By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy
4.7	By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture's contribution to sustainable development
4.a	Build and upgrade education facilities that are child, disability and gender sensitive and provide safe, nonviolent, inclusive and effective learning environments for all
4.b	By 2020, substantially expand globally the number of scholarships available to developing countries, in particular least developed countries, small island developing States and African countries, for enrolment in higher education, including vocational training and information and communications technology, technical, engineering and scientific programmes, in developed countries and other developing countries
4.c	By 2030, substantially increase the supply of qualified teachers, including through international cooperation for teacher training in developing countries, especially least developed countries and small island developing states.
5.1	End all forms of discrimination against all women and girls everywhere
5.2	Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation
5.3	Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation

Target Code	Target Description
5.4	Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of public services, infrastructure and social protection policies and the promotion of shared responsibility within the household and the family as nationally appropriate
5.5	Ensure women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life
5.6	Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the programme of action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform for Action and the outcome documents of their review conferences
5.a	Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws
5.b	Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology, to promote the empowerment of women
5.c	Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels
6.1	By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all
6.2	By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations
6.3	By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse globally
6.4	By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity
6.5	By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including through trans boundary cooperation as appropriate
6.6	By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes
6.a	By 2030, expand international cooperation and capacity-building support to developing countries in water- and sanitation-related activities and programmes, including water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse technologies
6.b	Support and strengthen the participation of local communities in improving water and sanitation management.
7.1	By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and modern energy services
7.2	By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix
7.3	By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency

Target Code	Target Description
7.a	By 2030, enhance international cooperation to facilitate access to clean energy research and technology, including renewable energy, energy efficiency and advanced and cleaner fossil-fuel technology, and promote investment in energy infrastructure and clean energy technology
7.b	By 2030, expand infrastructure and upgrade technology for supplying modern and sustainable energy services for all in developing countries, in particular least developed countries, small island developing States and landlocked developing countries, in accordance with their respective programmes of support.
8.1	Sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances and, in particular, at list 7 percent gross domestic product growth per annum in the least developed countries
8.2	Achieve higher levels of economic productivity through diversification, technological upgrading and innovation, including through a focus on high-value added and labour-intensive sectors
8.3	Promote development-oriented policies that support productive activities, decent job creation, entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the formalization and growth of micro-, small- and medium-sized enterprises, including through access to financial services
8.4	Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in consumption and production and endeavour to decouple economic growth from environmental degradation, in accordance with the 10-year framework of programmes on sustainable consumption and production, with developed countries taking the lead
8.5	By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all women and men, including for young people and persons with disabilities, and equal pay for work of equal value
8.6	By 2020, substantially reduce the proportion of youth not in employment, education or training
8.7	Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labour in all its forms
8.8	Protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers, including migrant workers, in particular women migrants, and those in precarious employment
8.9	By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products
8.10	Strengthen the capacity of domestic financial institutions to encourage and expand access to banking, insurance and financial services for all
8.a	Increase Aid for Trade support for developing countries, in particular least developed countries, including through the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance to Least Developed Countries

Target Code	Target Description
8.b	By 2020, develop and operationalize a global strategy for youth employment and implement the global Jobs pact of the International Labour Organization
9.1	Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and transborder infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all
9.2	Promote inclusive and sustainable industrialization and, by 2030, significantly raise industry's share of employment and gross domestic product, in line with national circumstances, and double its share in least developed countries
9.3	Increase the access of small-scale industrial and other enterprises, in particular in developing countries, to financial services, including affordable credit, and their integration into value chains and markets
9.4	By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with increased resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes, with all countries taking action in accordance with their respective capabilities
9.5	Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially increasing the number of research and development workers per 1 million people and public and private research and development spending.
9.a	Facilitate sustainable and resilient infrastructure development in developing countries through enhanced financial, technological and technical support to African countries, least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States
9.b	Support domestic technology development, research and innovation in developing countries, including by ensuring a conducive policy environment for, inter alia, industrial diversification and value addition to commodities
9.c	Significantly increase access to information and communications technology and strive to provide universal and affordable access to the Internet in least developed countries by 2020.
10.1	By 2030, progressively achieve and sustain income growth of the bottom 40 per cent of the population at a rate higher than the national average
10.2	By 2030, empower and promote the social, economic and political inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status
10.3	Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by eliminating discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate legislation, policies and action in this regard
10.4	Adopt policies, especially fiscal, wage and social protection policies, and progressively achieve greater equality
10.5	Improve the regulation and monitoring of global financial markets and institutions and strengthen the implementation of such regulations
10.6	Ensure enhanced representation and voice for developing countries in decision-making in global international economic and financial institutions in order to deliver more effective, credible, accountable and legitimate institutions

Target Code	Target Description
10.7	Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned and well-managed migration policies
10.a	Implement the principle of special and differential treatment for developing countries, in particular least developed countries, in accordance with World Trade Organization agreements
10.b	Encourage official development assistance and financial flows, including foreign direct investment, to States where the need is greatest, in particular least developed countries, African countries, small island developing States and landlocked developing countries, in accordance with their national plans and programmes
10.c	By 2030, reduce to less than 3 per cent the transaction costs of migrant remittances and eliminate remittance corridors with costs higher than 5 per cent.
11.1	By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable housing and basic services and upgrade slums.
11.2	By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, person with disabilities and older person
11.3	By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, person with disabilities and older person
11.4	Strengthen efforts to protect and safeguard the world's cultural and natural heritage
11.5	By 2030, significantly reduce the number of deaths and the number of people affected and substantially decrease the direct economic losses relative to global gross domestic product caused by disasters, including water-related disasters, with a focus on protecting the poor and people in vulnerable situations
11.6	By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by paying special attention to air quality and municipal and other waste management
11.7	By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities
11.a	Support positive economic, social and environmental links between urban, peri-urban and rural areas by strengthening national and regional development planning
11.b	By 2020, substantially increase the number of cities and human settlements adopting and implementing integrated policies and plans towards inclusion, resource efficiency, mitigation and adaptation to climate change, resilience to disasters, and develop and implement, in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, holistic disaster risk management at all levels
11.c	Support least developed countries, including through financial and technical assistance, in building sustainable and resilient buildings utilizing local materials
12.1	Implement the 10-year framework of programmes on sustainable consumption and production, all countries taking action, with developed countries taking the lead, taking into account the development and capabilities of developing countries

Target Code	Target Description
12.2	By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources
12.3	By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses
12.4	By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals and all wastes throughout their life cycle, in accordance with agreed international frameworks, and significantly reduce their release to air, water and soil in order to minimize their adverse impacts on human health and the environment
12.5	By 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse
12.6	Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt sustainable practices and to integrate sustainability information into their reporting cycle
12.7	Promote public procurement practices that are sustainable, in accordance with national policies and priorities
12.8	By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with nature
12.a	Support developing countries to strengthen their scientific and technological capacity to move towards more sustainable patterns of consumption and production
12.b	Develop and implement tools to monitor sustainable development impacts for sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products
12.c	Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption by removing market distortions, in accordance with national circumstances, including by restructuring taxation and phasing out those harmful subsidies, where they exist, to reflect their environmental impacts, taking fully into account the specific needs and conditions of developing countries and minimizing the possible adverse impacts on their development in a manner that protects the poor and the affected communities
13.1	Strengthen resilience and adaptive capacity to climate related hazards and natural disasters in all countries.
13.2	Integrate climate change measures into national policies, strategies and planning.
13.3	Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning.
13.a	Implement the commitment undertaken by the developed country parties to the united nations framework convention on climate change to a goal of mobilizing jointly \$100 billion annually by 2020 from all sources to address the needs of developing countries in the context of meaningful mitigation action and transparency on implementation and fully operationalize the green climate fund through its capitalization as soon as possible.
13.b	Promote mechanisms for raising capacity for effective climate change-related planning and management in least developed countries and small island developing states, including focusing on women, youth and local and marginalized communities.
14.1	By 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, in particular from land-based activities, including marine debris and nutrient pollution

Target Code	Target Description
14.2	By 2020, sustainably manage and protect marine and coastal ecosystems to avoid significant adverse impacts, including by strengthening their resilience, and take action for their restoration in order to achieve healthy and productive oceans
14.3	Minimize and address the impacts of ocean acidification, including through enhanced scientific cooperation at all levels
14.4	By 2020, effectively regulate harvesting and end overfishing, illegal, unreported and unregulated fishing and destructive fishing practices and implement science-based management plans, in order to restore fish stocks in the shortest time feasible, at least to levels that can produce maximum sustainable yield as determined by their biological characteristics
14.5	By 2020, conserve at least 10 per cent of coastal and marine areas, consistent with national and international law and based on the best available scientific information
14.6	By 2020, prohibit certain forms of fisheries subsidies which contribute to overcapacity and overfishing, eliminate subsidies that contribute to illegal, unreported and unregulated fishing and refrain from introducing new such subsidies, recognizing that appropriate and effective special and differential treatment for developing and least developed countries should be an integral part of the World Trade Organization fisheries subsidies negotiation
14.7	By 2030, increase the economic benefits to Small Island developing States and least developed countries from the sustainable use of marine resources, including through sustainable management of fisheries, aquaculture and tourism
14.a	Increase scientific knowledge, develop research capacity and transfer marine technology, taking into account the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology, in order to improve ocean health and to enhance the contribution of marine biodiversity to the development of developing countries, in particular small island developing States and least developed countries
14.b	Provide access for small-scale artisanal fishers to marine resources and markets
14.c	Enhance the conservation and sustainable use of oceans and their resources by implementing international law as reflected in UNCLOS, which provides the legal framework for the conservation and sustainable use of oceans and their resources, as recalled in paragraph 158 of The Future We Want
15.1	By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland fresh water ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains and dry lands, in line with obligations under international agreements
15.2	By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally
15.3	By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world
15.4	By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their biodiversity, in order to enhance their capacity to provide benefits that are essential for sustainable development
15.5	Take urgent and significant action to reduce the degradation of natural habitats, halt the loss of biodiversity and, by 2020, protect and prevent the extinction of threatened species

Target Code	Target Description
15.6	Ensure fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization of genetic resources and promote appropriate access to such resources
15.7	Take urgent action to end poaching and trafficking of protected species of flora and fauna and address both demand and supply of illegal wildlife products
15.8	By 2020, introduce measures to prevent the introduction and significantly reduce the impact of invasive alien species on land and water ecosystems and control or eradicate the priority species
15.9	By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values into national and local planning, development processes, poverty reduction strategies and accounts
15.a	Mobilize and significantly increase financial resources from all sources to conserve and sustainably use biodiversity and ecosystems
15.b	Mobilize significant resources from all sources and at all levels to finance sustainable forest management and provide adequate incentives to developing countries to advance such management, including for conservation and reforestation
15.c	Enhance global support for efforts to combat poaching and trafficking of protected species, including by increasing the capacity of local communities to pursue sustainable livelihood opportunities
16.1	Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere
16.2	End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children
16.3	Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all
16.4	By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime
16.5	Substantially reduce corruption and bribery in all their forms
16.6	Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels
16.7	Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels
16.8	Broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of global governance
16.9	By 2030, provide legal identity for all, including birth registration
16.10	Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements
16.a	Strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent violence and combat terrorism and crime
16.b	Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development
17.1	Strengthen domestic resource mobilization, including through international support to developing countries, to improve domestic capacity for tax and other revenue collection

Target Code	Target Description
17.2	Developed countries to implement fully their official development assistance commitments, including the commitment by many developed countries to achieve the target of 0.7 per cent of gross national income for official development assistance (ODA/GNI) to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries; ODA providers are encouraged to consider setting a target to provide at least 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries
17.3	Mobilize additional financial resources for developing countries from multiple sources
17.4	Assist developing countries in attaining long-term debt sustainability through coordinated policies aimed at fostering debt financing, debt relief and debt restructuring, as appropriate, and address the external debt of highly indebted poor countries to reduce debt distress
17.5	Adopt and implement investment promotion regimes for least developed countries
17.6	Enhance North-South, South-South and triangular regional and international cooperation on and access to science, technology and innovation and enhance knowledge sharing on mutually agreed terms, including through improved coordination among existing mechanisms, in particular at the United Nations level, and through a global technology facilitation mechanism
17.7	Promote the development, transfer, dissemination and diffusion of environmentally sound technologies to developing countries on favorable terms, including on concessional and preferential terms, as mutually agreed
17.8	Fully operationalize the technology bank and science, technology and innovation capacity building mechanism for least developed countries by 2017 and enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology
17.9	Enhance international support for implementing effective and targeted capacity-building in developing countries to support national plans to implement all the Sustainable Development Goals, including through North-South, South-South and triangular cooperation
17.10	Promote a universal, rules-based, open, nondiscriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization, including through the conclusion of negotiations under its Doha Development Agenda
17.11	Significantly increase the exports of developing countries, in particular with a view to doubling the least developed countries' share of global exports by 2020
17.12	Realize timely implementation of duty-free and quota-free market access on a lasting basis for all least developed countries, consistent with World Trade Organization decisions, including by ensuring that preferential rules of origin applicable to imports from least developed countries are transparent and simple, and contribute to facilitating market access
17.13	Enhance global macroeconomic stability, including through policy coordination and policy coherence
17.14	Enhance policy coherence for sustainable development
17.15	Respect each country's policy space and leadership to establish and implement policies for poverty eradication and sustainable development

Target Code	Target Description
17.16	Enhance the Global Partnership for Sustainable Development, complemented by multi-stakeholder partnerships that mobilize and share knowledge, expertise, technology and financial resources, to support the achievement of the Sustainable Development Goals in all countries, in particular developing countries
17.17	Encourage and promote effective public, publicprivate and civil society partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships
17.18	By 2020, enhance capacity-building support to developing countries, including for least developed countries and small island developing States, to increase significantly the availability of high-quality, timely and reliable data disaggregated by income, gender, age, race, ethnicity, migratory status, disability, geographic location and other characteristics relevant in national contexts
17.19	By 2030, build on existing initiatives to develop measurements of progress on sustainable development that complement gross domestic product, and support statistical capacity-building in developing countries.

Sustainable Development Goals (SDGs)/ Targets- Mapping with CSS/ State Schemes, Interventions, Nodal Ministries/ Departments

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	End poverty in all its forms everywhere	Rural Development	1. National Urban Livelihood Mission (Core) 2. National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA) Core of the Core 3. National Rural Livelihood Mission (NRLM) Core 4. National Social Assistance Programme (NSAP) (M/o RE/M/o Finance) Core of the Core 5. National Land Record Management Programme (NLRMP)	1. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana 2. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana 3. Atal Pension Yojana (APY)	1. Rajasthan Rural Livelihood Project (RRLP) 2. Mitigating Poverty in Western Rajasthan (MPOWER) 3. Employment Link Skill Development Training Project 4. Mukhyamantri Samman Yojana (Old Age/Widow/Disable) 5. Palanhar Yojana 6. Employment Scheme for Minority Boys and Girls	1. Rajasthan Gramin Aajeevika Vikas Parishad (RGAVP) 2. Rajasthan Skill & Livelihood Development Corporation (RSLDC) 3. Rajasthan Rural Non-Farm Development Agency (RUDA) 4. Bhamashah Yojana (Financial Inclusion)	1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than \$1.25 a day	RD, HUPA, Skill Development & Entrepreneurship	RD, Labour, Employment & Skill Development, LSG
							1.2 By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions	RD, HUPA, Skill Development & Entrepreneurship	RD, Labour, Employment & Skill Development, LSG
							1.3 Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable	Social Justice & Empowerment, RD, Labour, WCD, Minority Affairs, Tribal Affairs	SJED, RD, Labour, Employment & Skill Development, TAD, WCD, Minority
							1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance	Agriculture & Cooperation, Land Resources, Drinking Water & Sanitation, HUPA, RD, Panchayati Raj, Urban Development	Agriculture, Water Resource, Cooperative, LSG, PHED, TAD, RD&PR, DES (Bhamashah)
							1.5 By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters	Home Affairs	RD&PR, Disaster Management & Relief, TAD, SJED
							1.a Ensure significant mobilization of resources from a variety of sources, including through enhanced development cooperation, in order to provide adequate and predictable means for developing countries, in	RD, HUPA	RD&PR, LSG

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							particular least developed countries, to implement programmes and policies to end poverty in all its dimensions		
							1.b Create sound policy frameworks at the national, regional and international levels, based on pro-poor and gender-sensitive development strategies, to support accelerated investment in poverty eradication actions	External Affairs, RD	
2	End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture	Agriculture & Farmers Welfare	1. National Food Security Mission (Core) 2. Mission for integrated Development of Horticulture 3. National Mission on Sustainable Agriculture 4. National Oilseed and Oil Palm Mission 5. National Mission on Agriculture Extension and Technology 6. Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) (ACA) (Core) 7. National Livestock Mission (Core) 8. Livestock Health and Disease Control (Core) 9. National Programme for Bovine Breeding and Dairy Development	1. Targeted Public Distribution System (TPDS) 2. National Nutrition Mission (NNM) (Core) 3. National Food Security Act (NFSA), passed in 2013 4. Mid-Day Meal Scheme	1. Establishment of Kishan Seva Kendra Cum Village Knowledge Center 2. Rajasthan Agriculture Competitiveness Project 3. Addition Subsidy for Solar Pump Set 4. Constructions of Godowns 5. Weather Based Crop Insurance Scheme 6. Modified National Agriculture Scheme 7. Establishment of Soil/ Fertilizer/ Pesticide Testing Laboratories 8. Interest Subvention on Crop Loan 9. Mini-kit Distribution 10. Maa-Badi Scheme 11. Infrastructure Facilities in the Mandi	1. Free Distribution of Ghee, Daal, Oil to Saharia (Only PVTGs) and Kathodi Tribal Families 2. Buffer Stocking of Fertilizer 3. Mukhyamantri Pasudhan Nishulk Dava Yojana 4. Bhamashah Yojana (PDS Distribution through PoS) 5. Gypsum Distribution for reclamation of alkali Soil 6. Development of Olive Oil & Dates Farm 7. Development of Floriculture Park 8. Establishment of ILD Centers on PPP 9. Akshay Klewa Programme for Urban Pooors	2.1 By 2030, end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in vulnerable situations, including infants, to safe, nutritious and sufficient food all year round	Consumer Affairs Food & Public Distribution, Tribal Affairs	Food & Civil Supplies, TAD, WCD
							2.2 By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the internationally agreed targets on stunting and wasting in children under 5 years of age, and address the nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating women and older persons	Health & FW, Ayush, WCD	Health & FW, Ayush, WCD
							2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers, including through secure and equal access to land, other productive resources and inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for value addition and non-farm employment	Agriculture & Cooperation, Chemicals & Fertilisers, Tribal Affairs	Agriculture, Horticulture, Cooperative, TAD
							2.4 By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production, that	Agriculture & Cooperation	Agriculture & Cooperative

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>help maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve land and soil quality</p> <p>2.5 By 2020, maintain the genetic diversity of seeds, cultivated plants and farmed and domesticated animals and their related wild species, including through soundly managed and diversified seed and plant banks at the national, regional and international levels, and promote access to and fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources and associated traditional knowledge, as internationally agreed</p> <p>2.a Increase investment, including through enhanced international cooperation, in rural infrastructure, agricultural research and extension services, technology development and plant and livestock gene banks in order to enhance agricultural productive capacity in developing countries, in particular least developed countries</p> <p>2.b Correct and prevent trade restrictions and distortions in world agricultural markets, including through the parallel elimination of all forms of agricultural export subsidies and all export measures with equivalent effect, in accordance with the mandate of the Doha Development Round</p>	<p>Agriculture & Cooperation Tribal Affairs</p> <p>Commerce External Affairs</p> <p>Commerce</p>	<p>Agriculture, Cooperative, TAD & Animal Husbandry</p>

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2.c Adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity markets and their derivatives and facilitate timely access to market information, including on food reserves, in order to help limit extreme food price volatility.	Agriculture & Cooperation	Agriculture Marketing Department/ Board
3	Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages	Health & Family Welfare	1. National Health Mission including NRHM (Core) 2. Human Resource in Health and Medical Education (Core) 3. National Mission on Ayush including Mission on Medical Plants (Core) 4. National AIDS &STD Control Programme 5. Integrated Child Development Service (ICDS) (Core)	1. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (2006) (Core)	1. Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana 2. Mukhyamantri Nishulk Janch Yojana 3. TB Control Programme in Scheduled & Saharia Tribal Areas 4. Bhamashah Swasthya Bima Yojana 5. Mukhyamantri Jeevan Raksha Kosh 6. Rajshree Yojana 7. Schemes through BOCWB a. Prasuti sahayata yojana b. Hitadhikari ki samanya athawa durghatna me mrityu ya ghayal hone ki dasa me sahayata yojna c. Silicosis pidit hitadhikariyon hetu sahayata yojna d. Nirman	1. Establishment of 7 Medical Colleges 2. Community based Management Malnutrition 3. Safe Motherhood Day & Prasuti Niyojan Diwas 4. Integrated Ambulance System for better management of pregnant women transport and other trauma/ NCD patients 5. E-upkaran for better biomedical equipment management system 6. Technological interventions for DBT to ASHAs/ beneficiaries of health schemes, ASHA soft/ OJAS/ BSBY software 7. Naya Savera for action against substance abuse 8. Use of Video conference for interacting with LHV/ ANM/ ASHA for giving them inputs about many RCH contents 9. Deployment of Additional Health Workers in Scheduled & Saharia Areas 10. Building & Other	3.1 By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births	Health & FW, Ayush, WCD, Tribal Affairs	Health & FW WCD
							3.2 By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live births	Health & FW, Ayush, WCD	Health & FW, Ayush, WCD
							3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases	Health & FW, Ayush, Tribal Affairs Drinking Water and Sanitation, Food Processing Industries	Health & FW, Ayush, TAD
							3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being	Health & FW, Ayush, WCD, Tribal Affairs	Health & FW, Ayush, WCD, TAD
							3.5 Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol	Home Affairs, Health & FW, Ayush	Health & Family Welfare
							3.6 By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents	Road Transport & Highways, Health & FW, Ayush	Transport, UDH, PWD & Health & FW
							3.7 By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national	Health & FW, Ayush	Health & FW, WCD

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Shramik Jeevan Bhavishya e. Nirman Shramik swasthaya Bima Yojna	Construction Workers Welfare Board (BOCWB) 11.The State Government has set the goal to reduce the road accident fatalities in the state by 20% of the base line figure of 2015, by 2020. 12.A lead agency has been constituted under the Transport Commissioner with members from stake holder departments. 13.Besides existing committees, a Sub Divisional Level Road Safety Committee under the chairmanship of SDM is also being formed. 14.Initiatives like making helmet compulsory for both two wheeler drivers as well as pillion riders, incorporation of road safety education in school syllabi etc. have been taken by State Government. 15.Promotion of Yoga, establishment of wellness centers, establishment of Ayurveda specialty centers 16.Establishment of continuous Air Ambient Quality Monitoring Stations (CAAQMS) at Jaipur & Jodhpur. 8	strategies and programmes 3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all 3.9 By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination 3.a Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control in all countries, as appropriate 3.b Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and non-communicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public health, and, in particular, provide access to medicines for all 3.c Substantially increase health financing and the recruitment, development, training and retention of the health workforce in developing countries, especially in least developed countries and small island developing States	Health & FW, Ayush, Tribal Affairs MoEF&CC, Health & FW, Ayush Health & FW, Ayush Health & FW, Ayush, Commerce Health & FW, Ayush	Health & FW, Ayush, TAD Environment, Pollution Control Board, Health & FW, Ayush, Mines & Geology Health & FW, Ayush Medical & Health Health & FW, Ayush

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>more stations are proposed</p> <p>17. Comprehensive Air Quality Study for Jaipur city is proposed – through IIT, Kanpur</p> <p>18. Online emission monitoring system for highly air polluting industries</p> <p>19. Center of Excellency on Environmental Issues</p>	3.d Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk reduction and management of national and global health risks	Health & FW, Ayush	Health & FW, Ayush
4	Ensure inclusive and equitable quality education and promote Lifelong learning opportunities for all	HRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarva Shiksha Abhiyan (Core) 2. National Programme Nutritional Support to Primary Education (MDM) (Core) 3. Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) (Core) 4. Support for Educational Development including Teachers Training & Adult Education (Core) 5. Scheme for providing education to Madrasas, Minorities and Disabled (Core of the Core) 6. Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA) (Core) 7. Umbrella scheme for Education of ST students (Core of the Core) 	1. Padhe Bharat Badhe Bharat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vivekanand Model School 2. Residential schools for Tribal students 3. Ashram hostels for Tribal students 4. Maa-badi Centers 5. Cycle distribution to girls 6. Scooty distribution to meritorious girl 7. Transport Voucher 8. Pre-matric (Class VI-VIII) scholarship to SC/ST 9. Anuprati Yojana 10. Scholarship & financial assistance schemes for tribal students 11. Palanhar Yojana 12. Devnarayan Yojana 13. Schemes through BOCWB <ol style="list-style-type: none"> a. Nirman Shramik Shiksha va Kaushal Vikas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rationalization of schools & teachers 2. Aadarsh Vidhyalaya at each Panchayat 3. Incentive for girl education 4. Sambalan Scheme for ensuring quality education 5. Pravesho-tsav in Government Schools 6. Free education to BPL children in Private Schools under RTE 7. MG community library for all students studying in Class I to XII in Govt. Schools 9. Building & Other Construction Workers Welfare Board (BOCWB) 10. Aao Kadam Badhaye Shakshar Desh Banaye 	4.1 By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and Goal-4 effective learning outcomes	School Education & Literacy, Tribal Affairs	School Education, TAD, SJED, Minority Affairs
							4.2 By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care and preprimary education so that they are ready for primary education	School Education & Literacy	WCD, TAD
							4.3 By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education, including university	Skill Development & Entrepreneurship, Higher Education, Tribal Affairs	Higher & Technical Education, TAD, Labour, Employment & Skill Development
							4.4 By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship	Skill Development & Entrepreneurship, Tribal Affairs	Higher & Technical Education, TAD, Industry (MSME), Labour, Employment & Skill Development, (RSLDC)
							4.5 By 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all levels of education and vocational training for the vulnerable,	School Education & Literacy, Skill Development & Entrepreneurship	School Education, Technical Education, TAD, SJED

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Yojna 14.Chief Minister Madrasa Modernization Scheme 15.Shakshar Bharat Programme in all district (except Kota)		including persons with disabilities, indigenous peoples and children in vulnerable situations 4.6 By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy 4.7 By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture's contribution to sustainable development 4.a Build and upgrade education facilities that are child, disability and gender sensitive and provide safe, nonviolent, inclusive and effective learning environments for all 4.b By 2020, substantially expand globally the number of scholarships available to developing countries, in particular least developed countries, small island developing States and African countries, for enrolment in higher education, including vocational training and information and communications technology, technical, engineering and scientific programmes, in developed countries and other developing countries 4.c By 2030, substantially increase the supply of qualified teachers, including through		
								School Education & Literacy	School Education & Literacy
								Skill Development & Entrepreneurship, Culture	Labour, Employment & Skill Development, Youth & Sports, Art & Culture
								School Education & Literacy, WCD, Higher Education	School Education & Literacy, WCD, Higher Education, TAD, SJED
								School Education & Literacy, Higher Education, External Affairs, Tribal Affairs	
								School Education & Literacy, Higher Education, External	

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							international cooperation for teacher training in developing countries, especially least developed countries and small island developing states.	Affairs	
5	Achieve gender equality and empower all women and girls	WCD	1. National Mission for Empowerment of Women including Indira Gandhi Matritav Sahyog Yojana (Core) 2. Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (SABLA) (Core)	1. Beti Bachao Beti Padhao 2. Sukanya Samridhi Yojana (Girl Child Prosperity Scheme) 3. Support to Training And Employment Programme For Women (STEP) 2014 4. Janani Suraksha Yojana (JSY) 5. SWADHAR 2011 (A scheme for women in difficult circumstances) 6. Kasturba Balika Vidyalay (KGBV)	1. Mukyamantri RajShree Yojana 2. Free girls education upto college/ university level 3. Grant-in-aid for community marriages Scheme 4. Women Self Help Group 5. Swavalamban (training & skill development for self-employment) 6. Cycle distribution to all girls student taking admission in class IX 7. Transport Boucher to girls student studying in class IX to XII 8. Scooty distribution to meritorious girls 9. Free Basic Computer Training to Women 10. Ashram hostels for tribal girls 11. Hostel for SC, ST and Minority Girls 12. Mukhya Mantri Balika Sambal Yojana 13. Swayam Siddha Yojan 14. Schemes through BOCWB a. Shubh Shakti Yojna	1. Bhamashah Yojana (Financial Inclusion & Women Empowerment) 2. Mahila Suraksha avam Salah Kendra 3. 24 hours women helpline 4. Self-defence training in girls schools 5. AMRITA Haat (For marketing of women SHG products) 6. Priydarshini Aadarsh Swayam Sahayata Samooh 7. Income generation activity training to women SHGs 8. Mission Gramya Shakti 9. Interest subvention on bank loan by WSHGs 10. Balika Shiksha Foundation (Award to meritorious girls & financial assistance to girls of the poor families for higher & technical education) 11. Aparajita Centre (one stop crisis management centre for women victims of domestic abuse and violence) 12. Gramin Balika Sanrakshan Evum Samman Yojana 13. Scholarship to girls students taking	5.1 End all forms of discrimination against all women and girls everywhere	WCD	WCD
							5.2 Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation	WCD	WCD
							5.3 Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation	WCD	WCD
							5.4 Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of public services, infrastructure and social protection policies and the promotion of shared responsibility within the household and the family as nationally appropriate	WCD	WCD
							5.5 Ensure women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision making in political, economic and public life	WCD	WCD
							5.6 Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform for Action and the outcome documents of their review conferences	Health & FW, WCD	Health & FW, WCD
							5.a Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land	WCD, Land Resource, Urban Development, HUPA	WCD, Cooperative, Planning

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						admission in Agriculture Stream 14. Building & Other Construction Workers Welfare Board (BOCWB)	and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws 5.b Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology, to promote the empowerment of women 5.c Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels	Telecommunication, WCD, DeTy WCD, Social Justice	WCD, RKCL WCD
6	Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all	Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation (MoWR, RD & GR)	1. National Rural Drinking water Programme (Core) 2. Nirmal Bharat Abhiyan (Core) 3. Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana 4. National River Conservation Programme (NRCP)	1. Namami Gange Integrated Ganga Conservation Mission 2. Inter-linking of rivers		1. Constitution of Rajasthan River Basin and Water Resources Planning Authority 2. Mukhyamantri Jal Swavalamban Abhiyan 3. Four Water Concept 4. Building bylaws for Water Recharge Structure 5. Mandatory Drip/Sprinkler Irrigation System in Narmada Command Area 6. Convergence through MGNAREGA for construction of farm pond/ diggies on individual land 7. Establishment of Community RO Water Plants in quality affected habitations 8. Online Effluent Quality Monitoring of highly polluting categories of industries 9. Monitoring of water bodies and ground	6.1 By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all 6.2 By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations 6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse globally 6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity 6.5 By 2030, implement integrated water resources management at	Drinking Water & Sanitation, WCD Drinking Water & Sanitation, RD, Panchayati Raj MoEF&CC, MoWR, RD&GR MoWR, RD&GR, Agriculture & Cooperation, Land Resources MoWR, RD&GR, Agriculture &	PHED, RD&PR PHED, RD&PR Environment, Water Resources, PHED Water Resources, PHED, Agriculture Water Resources, PHED,

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						water under NWQMP 10. Study of important lakes and water bodies to preparing comprehensive action plan for their scientific environmental management	all levels, including through transboundary cooperation as appropriate 6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes 6.a By 2030, expand international cooperation and capacity-building support to developing countries in water- and sanitation-related activities and programmes, including water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse technologies 6.b Support and strengthen the participation of local communities in improving water and sanitation management.	Cooperation, Land Resources MoEF&CC MoWR,RD&GR, Land Resources MoWR, RD&GR, Drinking Water & Sanitation, HUPA, MEA Panchayati Raj, MoWR, RD&GR, Drinking Water & Sanitation, HUPA, MEA	Agriculture, Industries Environment, Forest, Water Resources, RD&PR, PHED Water Resource, PHED, LSG & UDH, RD&PR RD&PR, PHED, LSG & UDH
7	Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all	Power	---	1. Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana 2. National Solar Mission-providing continuous power supply to rural India 3. India Energy Policy 4. Power (2015)-Electrification of the remaining 20,000 villages including off-grid Solar Power by 2020 5. Five new Ultra Mega Power	1. Feeder Improvement Programme (for 3-phase system in rural areas) 2. Sub-Station Improvement Programme 3. SPV Pumping System in Horticulture Sector (subsidy for SPV Pumps) 4. Electrification through Solar in rural areas 5. Energy Conservation Programme	1. UDAY (financially turn-around of Power Distribution companies) 2. Rajasthan Solar Energy Policy, 2013 3. PPP for transmission projects and establishment of GSSs 4. Creation of Rajasthan State Energy Conservation Fund	7.1 By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and modern energy services 7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix 7.3 By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency 7.a By 2030, enhance international cooperation to facilitate access to clean energy research and technology, including renewable energy,	Power, New & Renewable Energy Coal, Tribal Affairs Petroleum & Natural Gas New & Renewable Energy Power, Coal, New & Renewable Energy, Petroleum & Natural Gas Power, New & Renewable Energy Coal, Petroleum & Natural Gas	Energy, TAD Energy, Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited Energy, Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited Energy, Rajasthan Renewable Energy Corporation

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Projects, each of 4000 MW to be installed			energy efficiency and advanced and cleaner fossil-fuel technology, and promote investment in energy infrastructure and clean energy technology		Limited
							7.b By 2030, expand infrastructure and upgrade technology for supplying modern and sustainable energy services for all in developing countries, in particular least developed countries, small island developing States, and land-locked developing countries, in accordance with their respective programmes of support.	Power, Petroleum & Natural Gas, New & Renewable Energy	Energy, Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited
8	Promote sustained, inclusive and sustainable Economic growth, full and productive employment and decent work for all	Labour & Employment	1. National Service Scheme (NSS) 2. Skill Development Mission 3. Social Security for Unorganised Workers including Rashtriya Swastya Bima Yojana (Core)	1. Deendayal Upadhyaya Antodaya Yojana. 2. National Urban Development Mission	1. RRLP, MPOWER 2. Mukhya Mantri Kaushal Vikas Yojana 3. Skill Training for self employment of Tribal Youths 4. Bhamashah Rojgar Srajan Yojana 5. Employment Linked Skill Training Programme 6. Distribution of tool kit for self employment 7. Akshat Yojana – (Rajasthan unemployment scheme) 8. Salt labour welfare scheme 9. Mukhya Mantri Swavlamban Yojana 10. Employment Scheme for	1. Rajasthan Aajeevika Vikas Parishad 2. Rajasthan Mission on Livelihoods (RMO-L) 3. Rajasthan Skill & Livelihoods Dev. Coprn. (RSLDC) 4. RSLDC plan for special projects for innovative livelihood sectors through NIFT, ATDC, BSC institute limited. Mayor, Nicotas, Sangam textiles of Indian institute of Gems & Jewelry. 5. MoU signed with Multinational Companies such as Toyota, Samsung, L&T etc. for skill upgradation of ITI trainees. 6. MoU signed by DSEE with BSDC and Photonics Industries International Inc. for	8.1 Sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances and, in particular, at least 7 per cent gross domestic product growth per annum in the least developed countries	Labour & Employment, Finance, MosPI, RD, HUPA, Urban Development, Tribal Affairs	Industry Agriculture Labour, Employment, & Skill Development Rural Development UDH
							8.2 Achieve higher levels of economic productivity through diversification, technological upgrading and innovation, including through a focus on high-value added and labour-intensive sectors	Labour & Employment, Finance, MoSPI, MSME, Science & Technology	Labour, Employment, & Skill Development Industry/ MSME DoIT Mines & Geology
							8.3 Promote development-oriented policies that support productive activities, decent job creation, entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the formalization and growth of micro-, small- and medium-sized enterprises, including through access to financial services	Labour & Employment, Tribal Affairs	Labour, Employment, & Skill Development Industry/ MSME
							8.4 Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in consumption and	MoEF&CC	-

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Minority Boys & Girls 11. Schemes through BOCWB a. Nirman Shramik Auzar/Toolkit Yojna	skill development in emerging field of photonics and establishment of Skill University in PPP Mode. 7. MoU signed between DSEE and ILD to form Govt. run Skill University. 8. MoU signed between State of Rajasthan and Wadhvani Operating Foundation (WOF) to make Rajasthan a leader in job creation and talent development under "Smart State" initiative. 9. 35 it is/SDCs to have CISCO networking academies. 10. Establishment of Centre of Excellence in ITIs. 11. Launched Rajasthan Startup Policy. 12. Constitution of Rajasthan Craft Council. 13. Online Handmade in Rajasthan Portal (under preparation). 14. Rajasthan Pravasi Shramik Kalyan Prakoshth (Overseas placement bureo) 15. Bhamashah Yojana (Financial Inclusion) 16. Establishment of Central for Excellence for Tourism/ Hospitality Training at	production and endeavour to decouple economic growth from environmental degradation, in accordance with the 10-year framework of programmes on sustainable consumption and production, with developed countries taking the lead 8.5 By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all women and men, including for young people and persons with disabilities, and equal pay for work of equal value 8.6 By 2020, substantially reduce the proportion of youth not in employment, education or training 8.7 Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labour in all its forms 8.8 Protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers, including migrant workers, in particular women migrants, and those in precarious employment 8.9 By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products 8.10 Strengthen the capacity of domestic financial institutions to encourage and expand access to banking, insurance and financial	Labour & Employment, WCD, Tribal Affairs, Youth Affairs & Sports, Social Justice Labour & Employment, Skill Development & Entrepreneurship, Youth Affairs & Sports, Tribal Affairs Labour & Employment, WCD Labour & Employment Tourism, Textiles Finance	Labour, Employment, & Skill Development WCD, TAD, Youth & Sports, SJED Labour, Employment, & Skill Development WCD, TAD, Youth & Sports Labour, Employment, & Skill Development, SJED Labour, Employment, & Skill Development Tourism Bhamashah & e-Mitra (BC & Pay Point) Planning & DoIT

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Udaipur 17. Establishment of new ITIs in scheduled /SCSP /Minority area 18. On job training 19. Modernization of employment exchange into career centers 20. Establishment of Banking Correspondent & pay point at Gram Panchayat & below panchayat level 21. Establishment of District Rural Vocational training & Entrepreneurship development center for short term training programme. 22. Building & Other Construction Workers Welfare Board (BOCWB)	services for all 8.a Increase Aid for Trade support for developing countries, in particular least developed countries, including through the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance to Least Developed Countries 8.b By 2020, develop and operationalize a global strategy for youth employment and implement the Global Jobs Pact of the International Labour Organization.	Commerce Labour & Employment, Youth Affairs	- -
9	Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation	Commerce & Industry	1. Border Area Development Programme (BADP) (ACA) (MHA/M/o Finance) 2. National Handloom Development Programme 3. Catalytic Development Programme under Sericulture 4. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) (Core)	1. Pt. Deendayal Upadhyaya Shramev Jayate Karyakram 2. Minimum Government Maximum Governance 3. Make in India 4. Start Up India 5. Ease of doing business initiative 6. FDI Policy	1. Gramin Gaurav Path Yojana 2. East West Mega Highway 3. DMIC 4. Khushkhhera – Bhiwari-Neemrana Investment Region 5. Jodhpur-Pali – Marawar Industrial Area 6. State Road Fund (SRF) for Major District Roads (MDRs) 7. Special Priority Roads	1. Resurgent Rajasthan Partnership Summit 2. Rajasthan E-Governance IT & ITeS Policy 2015 3. Rajasthan Startup Policy-2015 4. Single window clearance 5. Make in Rajasthan 6. Amendment in labour laws 7. Rajasthan Special Investment Region of Ordinance 2015 8. Viability gap funding for air connectivity to tourist destinations & other important	9.1 Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and transborder infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all	Road Transport and Highways, Railways, Shipping, Steel, Civil Aviation	PWD, RD, GAD, UDH
							9.2 Promote inclusive and sustainable industrialization and, by 2030, significantly raise industry's share of employment and gross domestic product, in line with national circumstances, and double its share in least developed countries	DIPP, MoSPI, MSME, Corporate Affairs, Heavy Industries	Industry, MSME, DMIC
							9.3 Increase the access of small-scale industrial and other enterprises, in particular in	MSME, Tribal Affairs	MSME

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					8. Area development schemes – Dang, Magra, Mewat 9. MLA LAD 10. Guru Golwalkar Jan Bhagidari Yojana	places 9. PPP Roads 10. Development of State Highways & major district roads 11. Rajasthan Road Sector Modernization Project 12. Internet connectivity in rural areas (Atal Seva Kendra) 13. Formulating a “Start-Up Policy” for utilization of wastes – based on 3Rs’ (Reduce, Recycle & Recover)	developing countries, to financial services, including affordable credit, and their integration into value chains and markets 9.4 By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with increased resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes, with all countries taking action in accordance with their respective capabilities 9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially increasing the number of research and development workers per 1 million people and public and private research and development spending 9.a Facilitate sustainable and resilient infrastructure development in developing countries through enhanced financial, technological and technical support to African countries, least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States 18 9.b Support domestic technology development, research and innovation in developing countries, including by ensuring a conducive policy environment for, inter alia, industrial diversification and value addition to commodities	 MoEF&CC, DIPP Science Technology, HRD & External Affairs, RD Science Technology & Science Technology &	 Environment, Mines & Geology Science Technology, Higher Technical Education - Science Technology &

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							9.c Significantly increase access to information and communications technology and strive to provide universal and affordable access to the Internet in least developed countries by 2020.	Telecommunication	DoIT&C
10	Reduce inequality within and among countries	Social Justice & Empowerment	1. Multi Sectoral Development Programme for Minorities 2. Backward Regions Grant Fund (District Component) (ACA) (M/oPR/M/o Finance) 3. Scheme for Development of Scheduled Castes (Core of the Core) 4. Scheme for Development of Other Backward Classes and Denotified, Nomadic and Semi-nomadic Tribes. (Core of the Core) 5. Scheme for development of Economically Backward Classes (EBCs) 6. Backward Regions Grant Fund (BRGF) (State Component) (ACA)	1. Grants from Central Pool of Resources for North Eastern Region and Sikkim 2. Udaan Scheme for youth of Jammu & Kashmir 3. PAHAL- Direct Benefits Transfer for LPG(DBTL) consumers scheme 4. Give it Up Campaign (for LPG subsidy) 5. Mudra Yojana	1. Janjati Kalyan Nidhi 2. Sambal Gram Vikas 3. Grant under Article 275(1) 4. ACA to TSP 5. Devnarayan Yojana 6. Magra/ Mewat/ Dang Area Development Scheme	1. Bhamashah Direct Benefit Transfer Scheme (Cash & Non-Cash Benefits) 2. Sahariya Vikas Samittee	10.1 By 2030, progressively achieve and sustain income growth of the bottom 40 per cent of the population at a rate higher than the national average	Finance, RD, HUPA, Urban Development, MSME, Tribal Affairs, Skill Development & Entrepreneurship	Labour, Employment & Skill Development, LSG, RD, MSME
							10.2 By 2030, empower and promote the social, economic and political inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status	Social Justice & Empowerment, Minority Affairs, Tribal Affairs, Development of North Eastern Region, Law & Justice	SJED, Minority Affairs, TAD, Law & Justice
							10.3 Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by eliminating discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate legislation, policies and action in this regard	Social Justice & Empowerment, Law & Justice, Tribal Affairs	SJED, TAD, Law & Justice
							10.4 Adopt policies, especially fiscal, wage and social protection policies, and progressively achieve greater equality	Social Justice & Empowerment, Tribal Affairs	SJED, TAD
							10.5 Improve the regulation and monitoring of global financial markets and institutions and strengthen the implementation of such regulations	Finance	-
							10.6 Ensure enhanced representation and voice for developing countries in decision-making in global international economic and financial institutions in order to deliver more effective, credible, accountable and	Finance	-

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							legitimate institutions		
							10.7 Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned and well-managed migration policies	Overseas Indian Affairs	-
							10.a Implement the principle of special and differential treatment for developing countries, in particular least developed countries, in accordance with World Trade Organization agreements	External Affairs, Commerce, DPP	-
							10.b Encourage official development assistance and financial flows, including foreign direct investment, to States where the need is greatest, in particular least developed countries, African countries, small island developing States and landlocked developing countries, in accordance with their national plans and programmes	Finance	Industry
							10.c By 2030, reduce to less than 3 per cent the transaction costs of migrant remittances and eliminate remittance corridors with costs higher than 5 per cent.	Finance	-
11	Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable	Urban Development	1. Rajiv Awas Yojana (including BSUP & IHSDP)	1. Smart Cities Mission (Core)	1. Housing for other indetified groups	1. Ring Road Jaipur	11.1 By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable housing and basic services and upgrade slums	HUPA, RD, Urban Development	RD, UDH, TAD
			2. Indira Awas Yojana (IAY)	2. Pradhan Mantri Awas Yojana (Housing for All-2022)	2. CM BPL Aawas	2. Rejuvenation and development of Dravyavati Nadi (Amanishah Nallah) Jaipur	11.2 By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and older persons	Road Transport & Highways, Railways	JMRC, UDH, LSG, Transport
			3. Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY)	3. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation	3. Mukhyamantri Jan Aawas Yojana (affordable housing in urban area)	3. Lake conservation project in Udaipur			
			4. National Programme for Persons with Disabilities		4. Housing for Sahariya tribals	4. Rajasthan Heritage Conservation and Development Authority			
			5. Jawaharlal Nehru National Urban		5. Housing for Kathodi tribes	5. Jaipur/ Udaipur Smart City Limited			
					6. Schemes through BOCWB				

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Renewal Mission (JNNURM) (ACA)	(AMRUT) (Core) 4. Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY)	a. Nirman Shramik Sulabhya Avaas Yojna	6. Amber Development and Management Authority, Jaipur 7. Jaipur/ Jodhpur/ Ajmer/ Kota/ Udaipur City Transport Services Limited 8. Building & Other Construction Workers Welfare Board (BOCWB) 9. Under Rajasthan Lok Privahan Seva 476 routes were notified and 900 license to the buses have been issued and installation of GPS is under progress. 10. Various initiatives have been taken to improve the services through private sector Participation. 11. In more than 2000 buses cameras were installed looking at the women security. 12. Seats are reserved and fares are concessional for women and specially abled in buses of Rajasthan Parivahan Nigam. 13. In Jaipur city the process of applying intelligent transport is being initiated by Police Department.	11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management in all countries 11.4 Strengthen efforts to protect and safeguard the world's cultural and natural heritage 11.5 By 2030, significantly reduce the number of deaths and the number of people affected and substantially decrease the direct economic losses relative to global gross domestic product caused by disasters, including water-related disasters, with a focus on protecting the poor and people in vulnerable situations 11.6 By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by paying special attention to air quality and municipal and other waste management 11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities 11.a Support positive economic, social and environmental links between urban, peri-urban and rural areas by strengthening national and regional development planning 11.b By 2020, substantially increase the number of cities and human settlements adopting and implementing integrated policies and plans towards inclusion, resource efficiency, mitigation and adaptation to climate change,	HUPA Culture Home Affairs	UDH Art & Culture DM&R, UDH,
								MoEF&CC	Environment, LSG
								M/o Urban Development	UDH
								Urban Development, Rural Development, Panchayati Raj	RD&PR, UDH
								Urban Development	UDH, DM&R

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							resilience to disasters, and develop and implement, in line with the forthcoming Hyogo Framework, Holistic Disaster Risk Management at all levels		
							11.c Support least developed countries, including through financial and technical assistance, in building sustainable and resilient buildings utilizing local materials.	Finance, External Affairs	-
12	Ensure sustainable consumption and production Patterns	MoEF&CC	---	1. National Policy on bio-fuels 2. National Clean India Fund (NCEF) 3. National Clean Energy Fund 4. Renewable Energy: Renewable Energy Global Investment Meet and Expo (RE-INVEST), Feb-2015 5. Soil Health Card Scheme (The schemes currently mentioned under this head could be shifted to goal 7)	1. SPV Pumping System in Horticulture Sector (Additional subsidy for SPV Pumps) 2. Electrification through Solar in rural areas 3. Additional subsidy on drip & sprinkler irrigation 4. Soil Health Card (Fertility mapping) 5. Distribution of domestic CFL/ LED bulbs	1. Rajasthan Solar Energy Policy, 2013 2. Creation of Rajasthan State Energy Conservation Fund 3. Bio-fuel Authority 4. Establishment of Soil/ Pesticides/ Fertilizers Testing Laboratories 5. Setting up/ upgradation of 37 CETPs in Textile Processing Areas are under progress/ pipeline.	12.1 Implement the 10-year framework of programmes on sustainable consumption and production, all countries taking action, with developed countries taking the lead, taking into account the development and capabilities of developing countries	MoEF&CC	Environment, Energy, Agriculture
							12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources	MoEF&CC, Mines	Environment, Mines & Geology
							12.3 By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses	Consumer Affairs & Public Distribution, Food Processing Industries	Food & Civil Supplies, Agriculture
							12.4 By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals and all wastes throughout their life cycle, in accordance with agreed international frameworks, and significantly reduce their release to air, water and soil in order to minimize their adverse impacts on human health and the environment	MoEF&CC, Chemicals & Fertilizers	Environment, UDH, Industry
							12.5 By 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse	MoEF&CC, Urban Development, Rural Development	Environment, UDH, RD&PR

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							12.6 Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt sustainable practices and to integrate sustainability information into their reporting cycle	MoEF&CC, Corporate Affairs	Environment, Industry,
							12.7 Promote public procurement practices that are sustainable, in accordance with national policies and priorities	Finance	Finance
							12.8 By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with nature	MoEF&CC, Information & Broadcasting	Environment, DPR
							12.a Support developing countries to strengthen their scientific and technological capacity to move towards more sustainable patterns of consumption and production	MoEF&CC, Science & Technology	Environment, Science & Technology
							12.b Develop and implement tools to monitor sustainable development impacts for sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products	Tourism, MoEF&CC	Forest, Tourism, Art & Culture
							12.c Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption by removing market distortions, in accordance with national circumstances, including by restructuring taxation and phasing out those harmful subsidies, where they exist, to reflect their environmental impacts, taking fully into account the specific needs and conditions of developing countries and minimizing the possible adverse impacts on their development in a manner that protects the poor and the affected communities	Finance, Petroleum & Natural Gas	-

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Take urgent action to combat climate change and its impacts	MoEF&CC	---	1. National Action Plan on Climate Change 2. National Mission for a Green India, 3. National Solar Mission, 4. National Mission for Enhanced Energy Efficiency, 5. National Mission for Sustainable Habitat, 6. National Water Mission, 7. National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem, 8. National Mission for Sustainable Agriculture and 9. National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change.	1. Climate Change and Combating desertification Scheme 2. Strengthening of Joint Forest Management 3. Rajasthan Forestry and Biodiversity Project (Phase II)	1. Rajasthan State Forest Policy, 2010 2. Mukhyamantri Jal Swavalamban Abhiyan 3. Constitution of State Compensatory afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) 4. Rathambhore Tiger Conservation Foundation 5. Rajasthan Protected Area Conservation Society 6. Rajasthan Solar Energy Policy, 2013 7. Creation of Rajasthan State Energy Conservation Fund 8. Bird Relief Centres and Godawans Conservation 9. Establishment of Biological Park at Udaipur/ Jaipur/ Jodhpur/ Bikaner 10. Establishment of Herbal Park at Pushkar 11. Prepared 'Rajasthan State Action Plan on Climate Change'	13.1 Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters in all countries	Home Affairs	Environment, DM&R
							13.2 Integrate climate change measures into national policies, strategies and planning	MoEF&CC	Environment
							13.3 Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning	MoEF&CC, Information & Broadcasting	Environment, Forest, DPR
							13.a Implement the commitment undertaken by developed-country parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change to a goal of mobilizing jointly \$100 billion annually by 2020 from all sources to address the needs of developing countries in the context of meaningful mitigation actions and transparency on implementation and fully operationalize the Green Climate Fund through its capitalization as soon as possible	MoEF&CC	Environment, Forest,
							13.b Promote mechanisms for raising capacity for effective climate change-related planning and management in least developed countries and small island developing States, including focusing on women, youth and local and marginalized communities	MoEF&CC	Environment, Forest
14	Conserve and Sustainably use the oceans, seas and marine resources for	Earth Sciences	1. Conservation of Natural Resource and EcoSystems	1. National Plan for Conservation of Aquatic Eco-System 2. Sagarmala			14.1 By 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, in particular from land-based activities, including marine debris and nutrient pollution	Earth Science, MoEF&CC	Fisheries

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sustainable development			Project (Blue Revolution)			14.2 By 2020, sustainably manage and protect marine and coastal ecosystems to avoid significant adverse impacts, including by strengthening their resilience, and take action for their restoration in order to achieve healthy and productive oceans	Earth Science, MoEF&CC	
							14.3 Minimize and address the impacts of ocean acidification, including through enhanced scientific cooperation at all levels	Earth Science, MoEF&CC	
							14.4 By 2020, effectively regulate harvesting and end overfishing, illegal, unreported and unregulated fishing and destructive fishing practices and implement science-based management plans, in order to restore fish stocks in the shortest time feasible, at least to levels that can produce maximum sustainable yield as determined by their biological characteristics	Deptt. of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (DADF)	Fisheries
							14.5 By 2020, conserve at least 10 per cent of coastal and marine areas, consistent with national and international law and based on the best available scientific information	MoEF&CC, Science & Technology, Deptt. of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (DADF)	
							14.6 By 2020, prohibit certain forms of fisheries subsidies which contribute to overcapacity and overfishing, eliminate subsidies that contribute to illegal, unreported and unregulated fishing and refrain from introducing new such subsidies, recognizing that appropriate and effective special and differential treatment for developing and least developed countries should be an integral part of the World Trade Organization fisheries subsidies negotiation	Deptt. of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (DADF)	

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							14.7 By 2030, increase the economic benefits to Small Island developing States and least developed countries from the sustainable use of marine resources, including through sustainable management of fisheries, aquaculture and tourism	Deptt. of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (DADF) Tourism	
							14.a Increase scientific knowledge, develop research capacity and transfer marine technology, taking into account the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology, in order to improve ocean health and to enhance the contribution of marine biodiversity to the development of developing countries, in particular small island developing States and least developed countries	Earth Science	
							14.b Provide access for small-scale artisanal fishers to marine resources and markets	Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (DADF)	
							14.c Enhance the conservation and sustainable use of oceans and their resources by implementing international law as reflected in UNCLOS, which provides the legal framework for the conservation and sustainable use of oceans and their resources, as recalled in paragraph 158 of The Future We Want.	Earth Science	
15	Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems,	MoEF&CC	1. National Afforestation Programme (National Mission for a Green India) (Core) 2. Integrated Development of Wild Life Habitats (Core)	1. Project Elephant 2. National Environmental Policy 2006 3. National Agroforestry	1. Rajasthan Bio-diversity Board 2. Climate Change and Combating desertification Scheme 3. Strengthening of	1. Rajasthan State Forest Policy, 2010 2. Mukhyamantri Jal Swavalamban Abhiyan 3. Constitution of State Compensatory afforestation Fund	15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains and dry lands, in line with obligations	MoEF&CC	Forest, Environment

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sustainably manage forests, combat desertification , and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss		3. Project Tiger (Core)	4. Policy (2014) National Action Programme to Combat Desertification(2001)	Joint Forest Management 4. Rajasthan Forestry and Biodiversity Project (Phase II) 5. Forest demarcation and settlement 6. Re-forestation of degraded forests 7. Farm Forestry 8. Eco- Tourism 9. Canal Area Afforestation 10.Environment Education and Awareness Programme	Management and Planning Authority (CAMPA) 4. Rathambhore Tiger Conservation Foundation 5. Rajasthan Protected Area Conservation Society 6. Bird Relief Centres and Godawans Conservation 7. Establishment of Biological Park at Udaipur/ Jaipur/ Jodhpur/ Bikaner	under international agreements		
							15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally	MoEF&CC Tribal Affairs	Forest, Environment
							15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world	Agriculture & Cooperation, Land Resources	-
							15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their biodiversity, in order to enhance their capacity to provide benefits that are essential for sustainable development	MoEF&CC Tribal Affairs	-
							15.5 Take urgent and significant action to reduce the degradation of natural habitats, halt the loss of biodiversity and, by 2020, protect and prevent the extinction of threatened species	MoEF&CC	Forest
							15.6 Ensure fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization of genetic resources and promote appropriate access to such resources	MoEF&CC Tribal Affairs	Forest, TAD
							15.7 Take urgent action to end poaching and trafficking of protected species of flora and fauna and address both demand and supply of illegal wildlife products	MoEF&CC	Environment, Forest, Mines & Geology, TAD
							15.8 By 2020, introduce measures to prevent the introduction and significantly reduce the impact of invasive alien species on land and water ecosystems and control or	MoEF&CC	Environment, Forest

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							eradicate the priority species		
							15.9 By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values into national and local planning, development processes, poverty reduction strategies and accounts	MoEF&CC Panchayati Raj, RD Tribal Affairs	Environment, Forest, Panchayati Raj
							15.a Mobilize and significantly increase financial resources from all sources to conserve and sustainably use biodiversity and ecosystems	MoEF&CC Finance	Environment, Forest
							15.b Mobilize significant resources from all sources and at all levels to finance sustainable forest management and provide adequate incentives to developing countries to advance such management, including for conservation and reforestation	MoEF&CC Ministry of Finance Tribal Affairs	Forest
							15.c Enhance global support for efforts to combat poaching and trafficking of protected species, including by increasing the capacity of local communities to pursue sustainable livelihood opportunities	MoEF&CC	Forest
16	Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels	Home Affairs	1. Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA) 2. Development of Infrastructure Facilities for Judiciary including Gram Nyayalayas (Core) 3. Integrated Child Protection Scheme (ICPS) (Core)	1. Digital India 2. Pragati Platform (Public Grievance Redressal System) 3. RTI (Right to Information Act)	1. Development of Infrastructure & basic facilities in courts. 2. Development of stadiums 3. Organizing State/District level games	1. Rajasthan Sampark Portal (for redressal of public grievances) 2. Nyaya Aapke Dwar Abhiyan (for redressal of Revenue related issues & matters) 3. Sarkar Aapke Dwar Abhiyan 4. Aapka Zila Aapki Sarkar 5. Establishment of new Child Empowerment Department 6. Rajasthan State Child protection Society 7. Constitution of CLG at Police Stations	16.1 Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere	Home Affairs	Home
							16.2 End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children	Home Affairs	SJED, Home
							16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all	Home Affairs Law & Justice	Home
							16.4 By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime	Home Affairs	Home
							16.5 Substantially reduce	Home Affairs	Anti-Corruption

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						8. Free Wifi at important Public Places	corruption and bribery in all their forms		Bureau
						9. Deployment of CCTV Cameras	16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels	Home Affairs	Administrative Reforms
						10. Development of online "Anti-Corruption Bureau Management System" (under preparation) – 16.5	16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels	Personnel, Public Grievances and Pensions, HUPA, RD, Panchayati Raj	DoP, Administrative Reforms, Finance, RD&PR
						11. Opening new family courts	16.8 Broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of global governance	External Affairs	-
						12. Organizing of Sports Competition across State	16.9 By 2030, provide legal identity for all, including birth registration	Home Affairs, Panchayati Raj	Planning, LSG, Panchayati Raj
						13. Identification and training to potential sports person for National & International competitions	16.10 Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements	Home Affairs, MEA	Administrative Reforms
						14. Creating world class sports infrastructure at district levels	16.a Strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent violence and combat terrorism and crime	Home Affairs MEA	-
							16.b Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development	Home Affairs	Home, Law & Justice, SJED
17	Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable Development	1. Finance	1. Support for Statistical Strengthening	1. South-South Cooperation 2. India Africa Summit 3. SCO (Shanghai Cooperation Organisation) 4. BRICS (Brazil, Russia, India, China, and		1. The capacity for the Tax and other Revenue collection increased through the use IT friendly processes. (17.1) • Online Application for Liquor groups/shops • E-Auction for grant of mining lease/	Finance 17.1 Strengthen domestic resource mobilization, including through international support to developing countries, to improve domestic capacity for tax and other revenue collection	Finance Corporate Affairs	Finance
							17.2 Developed countries to implement fully their official development assistance commitments, including the	Finance, MEA	Finance

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				South Africa) 5. NDB (New Development Bank– BRICS) 6. SAARC Satellite (South Asian Association for Regional Cooperation)		quarry license for Major Minerals • Online collection of VAT and Stamp Duty 2. Continuous interventions for increasing Tax base, Rationalization of Tax Rate/exemptions, simplification of Tax Collection processor, steps for curving revenue leakage and specific efforts for additional Revenue Mobilization. (17.3) 3. Higher Taxation on the demerit goods. (17.3) 4. Amnesty Scheme for various State Taxes and Duties. (17.3)	commitment by many developed countries to achieve the target of 0.7 per cent of ODA/GNI to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries ODA providers are encouraged to consider setting a target to provide at least 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries		
							17.3 Mobilize additional financial resources for developing countries from multiple sources	Finance	Finance
							17.4 Assist developing countries in attaining long-term debt sustainability through coordinated policies aimed at fostering debt financing, debt relief and debt restructuring, as appropriate, and address the external debt of highly indebted poor countries to reduce debt distress	MEA, Finance	Finance
							17.5 Adopt and implement investment promotion regimes for least developed countries	MEA, Information & Broadcasting	-
		2. Science & Technology	---	---			Technology 17.6 Enhance North-South, South-South and triangular regional and international cooperation on and access to science, technology and innovation and enhance knowledge sharing on mutually agreed terms, including through improved coordination among existing mechanisms, in particular at the United Nations level, and through a global technology facilitation mechanism	MEA, Information & Broadcasting	Science & Technology
							17.7 Promote the development, transfer, dissemination and diffusion of environmentally sound	MoEF&CC, Science & Technology	Science & Technology

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							technologies to developing countries on favourable terms, including on concessional and preferential terms, as mutually agreed		
							17.8 Fully operationalize the technology bank and science, technology and innovation capacity-building mechanism for least developed countries by 2017 and enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology	Science & Technology Telecommunication	Science & Technology, DoIT&C
		3. MEA	---	---			Capacity Building 17.9 Enhance international support for implementing effective and targeted capacity-building in developing countries to support national plans to implement all the sustainable development goals, including through North-South, South-South and triangular cooperation	MEA, RD	-
		4. Commerce & Industry	---	---			Trade 17.10 Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization, including through the conclusion of negotiations under its Doha Development Agenda	Commerce	-
							17.11 Significantly increase the exports of developing countries, in particular with a view to doubling the least developed countries' share of global exports by 2020	Commerce	-
							17.12 Realize timely implementation of duty-free and quota-free market access on a lasting basis for all least developed countries, consistent with World Trade Organization	Commerce, DIPP	-

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							decisions, including by ensuring that preferential rules of origin applicable to imports from least developed countries are transparent and simple, and contribute to facilitating market access		
		5. Finance	---	---			Policy and Institutional Coherence 17.13 Enhance global macroeconomic stability, including through policy coordination and policy coherence	Finance, MoSPI	-
							17.14 Enhance policy coherence for sustainable development	MoEF&CC	-
							17.15 Respect each country's policy space and leadership to establish and implement policies for poverty eradication and sustainable development	MEA, Rural Development	-
		6. MOEF&C C	---	---			Multi-Stakeholder Partnerships 17.16 Enhance the global partnership for sustainable development, complemented by multi-stakeholder partnerships that mobilize and share knowledge, expertise, technology and financial resources, to support the achievement of the sustainable development goals in all countries, in particular developing countries	MoEF&CC, Information & Broadcasting	-
							17.17 Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships.	Finance	-
		7. MOSPI	---	---			Data, Monitoring & Accountability 17.18 By 2020, enhance capacity-building support to developing countries, including for least developed countries and small island developing States, to	MoSPI	Planning DoIT&C

Goal No.	Goal	Nodal Ministry	Centrally Sponsored Schemes (CSS)	Related Interventions	State Schemes	State's Intervention	Targets	Other concerned Ministries/Departments	Concerned Depts. of the State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							increase significantly the availability of high-quality, timely and reliable data disaggregated by income, gender, age, race, ethnicity, migratory status, disability, geographic location and other characteristics relevant in national contexts		
							17.19 By 2030, build on existing initiatives to develop measurements of progress on sustainable development that complement gross domestic product, and support statistical capacity-building in developing countries.	MoSPI	Planning